DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS (GENERAL), 1969-70—contd.

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : चेयरमैन महोदय, मैंने श्री मधु लिमये जी की स्पीच बड़े ध्यान से सुनी । मुझे उन पर रहम आता है । उनकी हालत उस बन्दर की है जो गाड़ी के नीचे-नीचे चल रहा था और यह कहता था कि यह गाड़ी मेरे दम से चल रही है । उनको गलत ख्वाब हो गया कि इस देश में सोशलिज्म के ठेकेदार वही हैं और जो वह कह दें वही हदीस बन जाता है । सोशलिज्म की बावत वे समझते हैं किसी को भी—ट्रेजरी बेंचेज और अपोजीशन—कोई हक नहीं है । उन्होंने शिकायत कर दी कि रेडियो पर सारा जिक्र प्राइम मिनिस्टर का ही होता है । मेरी शिकायत गवर्नमेंट से यह है कि बहुत ज्यादती की जाती है,पार्लियामेन्ट का जो वक्त होता है उसमें 50 फीसदी मधु लिमये के लिए रहता है । रेडियो पर किसान, हरिजन और बैकवर्ड की बातें नहीं रखी जाती हैं । तो पहले तो मैं इनफ़ौर्मेशन मिनिस्टर और आप की मार्फत प्रैस से यह कहना चाहता हूं कि आधे से ज्यादा टाइम और अखबारों में जगह जो इन को दी जाती है, यह बेकार है । इस को क्या आप ने लाल भुजक्कड़ बना रखा है । इस हाउस में जानबूझकर गलत तौर पर बुरी नीयत से हमारी प्राइम मिनिस्टर के ऊपर रकीक हमले किए जाते हैं जो सरासर गलत हैं । आज तो देश एक दोराहे पर खड़ा है एक चीज़ चल दी है और हमें यह तय करना है कि सरमायेदारी के साथ चलना है या गरीबी के साथ चलना है । आज कांग्रेस पार्टी ने एक इनक्लाबी रोल अदा किया है और यह समझते हैं कि हमारी दुकान का क्या बनेगा । माल है ही नहीं दुकान में, बनेगा क्या ? बहुत दिन सोशलिज्म के नाम से इन्होंने लोगों को बहकाया है । सोशलिज्म का हमारा 10 पौइंट प्रोग्राम है जिस को हमारी प्राइम मिनिस्टर पूरा करने चली हैं । अभी अर्बन सीलिंग आयेगा, फ़ौरेन ट्रेड का नेशनेलाइज़ेशन आयेगा, जनरल इन्श्यौरेंस का नेशनेलाइज़ेशन आयेगा, प्लान्टेशन का नेशनेलाइज़ेशन आयेगा और पैरिटी आफ़ इन्कम होगी । सभापति जी, मुझे इन पर रहम आता है यह बेचारे रो रहे हैं कि हाय हमारा क्या बनेगा ? इन के खोखे का भट्टा बैठ जायेगा । कांग्रेस की शानदार दुमन्जली दूकान के सामने इन्होंने अपना खोखा रख रखा है । इन की दूकान को कौन पूछेगा , माननीय मधु लिमये जी को कौन पूछेगा ? इसलिये मातम मच गया है । हमारी प्राइम मिनिस्टर ने एक तहरीकी फ़ैसला किया है । हम गरीब जनता के साथ हैं । कंवर लाल गुप्ता जी ने भी सोशलिज्म पढ़ना शुरू कर दिया है, जनसंघ वाले भी सोशलिज्म की बात करने लगे हैं । यह बिल्ली हज को चलने लगी है । देखना है कि गुप्ता जी की पार्टी और स्वतंत्र पार्टी में कौन सा सोशलिज्म बनेगा । हम तो चाहते हैं कि हमारे समाजवादी प्रोग्राम के साथ इन का टकराव हो ।

जो रकीक हमले हमारी प्राइम मिनिस्टर पर किये जा रहे हैं वे कंडमनेबिल हैं । क्या बात कही कि बिड़ला की रोटी पर तुम तो मलाई की बात कहते हो । चेयरमैन साहब, हम तो रोटी को छीनना चाहते हैं । और सब में बराबर बांटना चाहते हैं । हम सब को बराबर बना देंगे, इस तरह से कांग्रेस का प्रोग्राम चलेगा और उस तरफ़ हमारी प्राइम मिनिस्टर ने मजबूती से कदम उठाया है । हिन्दुस्तान आज जाग गया है ।

प्रधान मंत्री के घर पर क्या यों ही आदमी जा रहे हैं । यह एक तहरीक है, और बगैर जूते पहने हुए पैदल आदमी प्राइम मिनिस्टर के घर पर जा रहे हैं । यह कोई मामूली बात है । मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस की जिन्दगी सौ साल और बढ़ गयी है और इन को पता लग गया है :

"सचाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से,
खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से ।"

ये विरोधी दल वाले कागज़ के फूल लिये बैठे हैं । अभी इन को बहुत दुख होगा जैसे-जैसे हमारे प्रोग्राम को देखेंगे । आप उधर से इधर आ जावो, हम आपके हलवे मांडे का बन्दोवस्त कर देंगे । अब आप की दुकान का भट्टा बैठ

गया है इसलिये आप इधर आ जाइये और हमारे साथ जनता की सेवा कीजिये ।

चेयरमैन साहब, मैं आप का मशकूर हूं कि आप ने मुझे मौका दिया ।

SHRI E. K. NAYANAR (Palghat): The supplementary demands presented to the House clearly show that there is absolutely no basic change in the economic policies of the Government despite tall claims made to that effect.

People were expecting certain radical measures as a follow-up action after the nationalisation of major banks. But their hopes have been belied due to the refusal of Government to take stringent measures against the big business.

If the Government is under the impression that people can be fed for a long time on verbal promises or formal talk against big business, it is greatly mistaken.

The demands highlight the glaring fact that the bureaucracy is even now being allowed to play havoc with public funds and get away without any punishment. I am surprised to find that the Government has to pay Rs. 2 lakhs more from the public funds due to bungling by some officials of the stationery and printing department. The Government is making additional payment but what about the punishment to the officials responsible for this sorry state of affairs? I only hope that the Government would go into the details of the matter.

Recently, the Report of the Licensing Committee has brought to the forefront the fact that the entire official machinery was utilised by various big business houses to add to their super-profits. This is a very serious matter but the Government refuses to move, with the result that the big business is likely to get away with all the ill-gotten wealth earned in the past.

If the Government is really serious about taking action on the report, it should first take stringent action against all the big business houses who have misused the state apparatus for their selfish ends.

Despite glib talk, the Government has not taken any steps to crush big business and curb monopolists. I therefore have a feeling that if further measures are not taken, the big business may use the nationalised banks for their benefits. The experience of working the LIC, SBI and official financing agencies clearly shows how the nationalised institutions are being used by big business.

If the Government takes further measures like a moratorium on foreign debt payments, ban on export of profits by foreign companies, nationalisation of export|import trade and foreign oil companies, it would make available huge funds with the Government which can be used for small industries and agriculture.

Distribution of land to the agricultural workers would help in reorienting the rural economy and create additional market for our industries. Even after 22 years, most of the States have not implemented land reform legislation suggested by the Planning Commission and distributed waste land to agricultural workers. I do not want to increase the list, but some such measures are immediately called for which alone can help us build a self-reliant economy.

The Government however, has not given any indication to go ahead in this direction. I have no doubt that the people of this country will bring sufficient pressure on Government and see that these and similar measures are forced on the Government which has brought the economy to such chaos and disaster.

Regional imbalances and discrimination against States still continue. To give an example, take the question of the industrial development of Kerala. After three Five Year Plans, what is the position there? Where is the shipyard promised? A provision of Rs. 2 crores was made in the Third Plan, but *not a single*

(Shri E. K. Nayanar)

pie was spent. Where is the Precision Tool Factory in Palghat which was accepted in the Third Plan? We do not know when it is coming.

One right steps has been taken by the nationalisation of banks. But regional imbalances continue. Government should push on with radical steps to help the States which are backward to develop industrially so that regional imbalance is removed and the people of the States benefit.

MR. CHAIRMAN: This item was considered by the Business Advisory Committee and that Committee gave one hour and the House has approved of it. We are hearing 5.39.

SHRI J. M. BISWAS: At least give a chance to one spokesman from each party. The CPI, DMK and the PSP have not spoken.

MR. CHAIRMAN: I shall stick to the time.

SHRI LOBO PRABHU: We never observed the time limit . . . (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Time is precious. I cannot allow more time; even if I can I do not want to increase the time. The time must be adhered to. This is the first thing that we have to learn. We never adhere to time here and we are doing it over and over again.

श्री रामावतार शास्त्री : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। जब भी यहां बहस होती है हमारे प्रतिनिधि को मौका मिलता रहा है। इस पर हमारी पार्टी का कोई प्रतिनिधि नहीं बोला है। उसको मौका मिलना चाहिए। सब पार्टीज को आपने मौका दिया। हमें भी मिलना चाहिये।

MR. CHAIRMAN: The allotted time should be adhered to.

श्री मधु लिमये : आधा घंटा आप बढ़ा सकते हैं। आप आधा घंटा बढ़ा दीजिये।

श्री रामावतार शास्त्री : हमारी पार्टी का यह सवाल है, हमारे अधिकारों का यह सवाल है . . . . .***

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : जिन सप्लीमेंटरी डिमांड्ज को लेकर हम सदन के सामने आये थे उनकी चर्चा माननीय सदस्यों ने नहीं की है। विशेषकर अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों के लोगों के विकास के लिये एक विशेष योजना के तहत चार ट्रेनिंग इंस्टीटयूट खोलने, मल्टी परपज रिवर स्कीमों की रिसर्च करने तथा स्माल स्केल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन के जरिये लघु उद्योगों के लिये सहायता देने कलकत्ता पोर्ट के विकास एवं हेसियन डिवलेपमेंट कमिश्न को कुछ सहायता देने आदि के सम्बन्ध में कुछ मांगें लेकर हम सदन के सामने आए थे। इन बातों की चर्चा न करके केवल राजनितिक मुद्दों की यहां पर चर्चा की गई है जिन का इन सप्लीमेंटरी डिमांड्ज से कोई सम्बन्ध नहीं है। यदि माननीय सदस्य शान्ति से सुनने के लिये तैयार होते तो एक एक करके मैं सब को उत्तर देने को तैयार था।

जो भी हो, कुछ माननीय सदस्यों ने ग्रामीण विकास और विशेषतः राजस्थान में रेगिस्तान के विकास, वहां पीने के पानी की व्यवस्था, देहातों में संचार व्यवस्था तथा महिदा साहब ने सिविल एवियेशन ट्रांसपोर्ट आदि के विकास की चर्चा की है। श्री ओंकर लाल बोहरा ने रेगिस्तान के बढ़ने की चर्चा की है। न केवल रेगिस्तान को रोकने के लिये बल्कि देश के सभी पिछड़े हुए इलाकों, पहाड़ी इलाकों को आगे लाने का प्रयास किया जा रहा है और समुचित योजना बनाकर उनकी कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। योजना आयोग ने इसलिये राष्ट्रीय विकास परिषद में जो फार्मूला तैयार किया है उसके तहत इन पिछड़े वर्गों के लिये राज्य सरकारों को सामान्य सहायता के अलावा दस प्रतिशत और सहायता इन पिछड़े हुए क्षेत्रों के लिये देने का फैसला किया है।

***Not recorded as ordered by the Chair.

माननीय सदस्य यदि पहली, दूसरी और तीसरी योजना के आंकड़े देखें तो उनको पता चलेगा कि जो बातें कहीं गई हैं उन सभी के लिये सरकार योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर रही है तथा चौथी योजना में इस बात का पूरा प्रयास किया जा रहा है कि जो कमियां अब तक रह गई हैं, उनको पूरा कर दिया जाये।

एक माननीय सदस्य ने लाइसेंसिंग इनक्वायरी की रिपोर्ट की चर्चा की है। वह रिपोर्ट सरकार को पिछले महीने प्राप्त हुई थी। हमने विभिन्न मंत्रालयों के रिएक्शन जानने के लिये उनके पास इस रिपोर्ट को भेज दिया है। जैसे ही उनसे हमको उनके विचार प्राप्त होंगे, इंडस्ट्रियल डिवेलेपमेंट कमेटी उन पर विचार कर उचित कार्यवाही करेगी।

एक माननीय सदस्य ने बिड़ला समूह की इनक्वायरी का भी जिक्र किया है। उस सम्बन्ध में सरकार विचार कर रही है कि क्या कदम उठाये जाने चाहियें।

देश के अन्दर व्याप्त बेकारी की आम चर्चा के अलावा देश में खास तौर पर इंजीनियरों की बेकारी की चर्चा की गई है। केवल इंजीनियरों की बेकारी ही नहीं, सभी प्रकार की बेकारी को मिटाने के लिये सरकार प्रयत्नशील है और इसलिये आपने देखा होगा कि उन लोगों को जिनके पास साधन नहीं हैं, उनके वास्ते साधन जुटाने की दृष्टि से सरकार ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया है और इस बात की घोषणा की है कि इससे प्राप्त पैसे से हम न केवल इंजीनियरों को बल्कि छोटे उद्योग धंधों में काम करने वालों और कुटीर उद्योगों में काम करने वाले लोगों को भी सहायता देने की योजना बना रहे हैं। वह योजना जैसे ही बनेगी, संसद् के सामने प्रस्तुत कर दी जायेगी। तब आप देखेंगे कि इस दिशा में सरकार के कदम निश्चित रूप से बेकारी को मिटाने में सहायक सिद्ध होते हैं।

अन्य बातों की चर्चा माननीय गुप्त जी ने की है फिर चाहे ए० आई० आर० से प्रधान मंत्री के वक्तव्यों को प्रसारित करने का सवाल हो और चाहे लिमये जी द्वारा समाचार पत्रों में किसी व्यक्ति विशेष को बढ़ाने घटाने का सवाल है, उन सवालों का इन सप्लीमैंटरी डिमांड्ज से कोई सम्बन्ध नहीं है। लेकिन सरकार की नीति यह रही है कि किसी के साथ कोई अन्याय न हो तथा किसी को भी कोई विशेष रियायत प्राप्त न हो। लेकिन चूंकि कुछ माननीय सदस्यों के दिमाग में विरोध करने के लिये कोई बात होनी चाहिये, इस वास्ते ऐसी भावना को लेकर उन्होंने इन सब बातों की चर्चा की है। हमारा प्रयास बराबर यह रहेगा कि जो सुझाव भी यहां दिये जायें उनकी हम जांच करें और अगर ठीक पाये जायें तो उन पर उचित कार्यवाही करने का प्रयास करें।

MR. CHAIRMAN: Now, I will put all the cut motions to the vote of the House.

SHRI LOBO PRABHU: Sir, I want division on the cut motions.

MR. CHAIRMAN: Let the lobbies be cleared.

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur): Sir, in this discussion DMK, CPI and other parties have not been given a chance to speak. As a protest, my colleagues have walked out. I am also walking out.

(Shri S. M. Banerjee left the House at this stage)

SHRI S. KANDAPPAN (Mettur): Sir, the way in which the business was conducted here was unfair, because some of the groups were not given any opportunity to put forward their case. At least the major groups should have been given an opportunity. Unfortunately, the procedure adopted was such that even DMK, with a strength of 25 members, was deprived of an opportunity to have its say. As a protest, we are abstaining from voting.

MR. CHAIRMAN: Now the lobbies have been cleared. Which of the cut motions does Shri Lobo Prabhu want to be put separately?

SHRI LOBO PRABHU: Let them all be put to vote by voice vote.

MR. CHAIRMAN: All right. I will not put all the cut motions to the vote of the House.

All the cut motions were put and negatived.

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That the respective Supplementary sums not exceeding the amounts shown in the third column of the order paper be granted to the President to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1970, in respect of the following demands entered in the second column thereof—

Demands Nos. 7, 44, 60, 61, 66, 82, 93, 98, 116, 121, 124, 125 and 131."

The motion was adopted.

17.34 hrs.

APPROPRIATION (NO. 4) BILL*, 1969.

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI JAGANNATH PAHADIA): On behalf of Shri Prakashchand B. Sethi, I beg to move for leave to introduce a Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 1969-70.

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 1969-70."

The motion was adopted.

SHRI JAGANNATH PAHADIA: I introduce† the Bill.

17.35 hrs.

POINT OF PERSONAL EXPLANATION

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY PLANNING AND WORKS, HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT (SHRI K. K. SHAH): Sir, in the morning Shri Prakash Vir Shastri stated on the floor of the House, when I was not present in the House, that I was a member of the Board of Trustees of Janahit Nidhi Trust. I wish to emphatically deny this allegation and regret that an hon. Member should have made such an unfounded statement. I request your permission to deny such a wild allegation.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (हापुड़) : सभापति महोदय, मैंने यह बात कही थी । लेकिन अगर आप उस के ट्रस्टी नहीं है, तो मैं इस के लिये दु:ख प्रकट करता हूं ।

17.36 hrs.

HALF-AN-HOUR DISCUSSION
NATIONAL TEXTILE CORPORATION

SHRI S. R. DAMANI (Sholapur): Sir, I am very grateful to you for giving me this opportunity to place before the Government the difficulties and hardships suffered by the families of hundreds and thousands of workers who have been thrown out of employment by the closure of so many mills in different parts of the country during the last few years. The mills which have gone out of commission and have broken down last year are mostly situated in small

*Published in Gazette of India Extraordinary, Part II, section 2, dated 25-8-69.

†Introduced with the recommendation of the Chief Justice of India discharging the functions of the President.